

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2438
जिसका उत्तर मंगलवार 2 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहन

2438. श्री दिनेश त्रिवेदी:

श्री शिवकुमार उदासि:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश में वर्ष 2030 तक सभी वाहनों को विद्युत चालित वाहन बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने विद्युत चालित वाहनों की बिक्री की गई है; और
- (ग) देश में विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : देश में वर्ष 2030 तक सभी वाहनों को विद्युत चालित वाहन बनाने की भारी उद्योग विभाग की फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) : गत तीन वर्षों के दौरान फेम-इंडिया स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्राप्त वाहनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

(ग) : भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने फेम-इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है, जिसका उद्देश्य हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और इसके विनिर्माणकारी पारिस्थितिकी-तंत्र को सहायता प्रदान करना है ताकि आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इस स्कीम के चार फोकस क्षेत्र हैं, यथा-प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना।

मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार सृजित करने का लक्ष्य वाहनों के सभी सेगमेंटों अर्थात्-दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह मांग प्रोत्साहन क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं) को क्रय मूल्य में शुरुआती कटौती के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग इन वाहनों को व्यापक रूप से अपनाएं।

इसके अतिरिक्त, अलग-अलग फोकस क्षेत्रों अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान एवं विकास); प्रायोगिक परियोजनाएं; चार्जिंग अवसंरचना के अंतर्गत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं/प्रस्तावों का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।

फेम-इंडिया स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्राप्त वाहनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा				
राज्य	सहायता प्राप्त वाहनों की कुल संख्या			सकल योग
	2015-16	2016-17	2017-18 (नवंबर, 2017)	अप्रैल, 15 से नवंबर, 17
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	46	29	-----	75
आंध्र प्रदेश	1351	2899	774	5024
असम	81	186	323	590
बिहार	371	414	477	1262
चंडीगढ़	633	1013	320	1966
छत्तीसगढ़	469	926	569	1964
दादरा और नगर हवेली	178	626	-----	804
दिल्ली	4200	10961	1624	16785
गोवा	137	334	3	474
गुजरात	7846	13686	3201	24733
हरियाणा	1978	4030	3240	9248
हिमाचल प्रदेश	22	69	-----	91
जम्मू और कश्मीर	65	117	57	239
झारखंड	257	501	144	902
कर्नाटक	3512	5488	969	9969
केरल	2744	4647	1077	8468
मध्य प्रदेश	880	2111	958	3949
महाराष्ट्र	8082	13120	1943	23145
मणिपुर	10	1	-----	11
मेघालय	5	-----	1	6
नगालैंड	1	-----	-----	1
ओडिशा	333	624	540	1497
पुदुचेरी	166	286	73	525
पंजाब	1517	2855	441	4813
राजस्थान	2413	4576	2336	9325
तमिलनाडु	2832	5822	1395	10049
तेलंगाना	2290	3919	626	6835
त्रिपुरा	2	6	21	29
उत्तर प्रदेश	3793	5729	3852	13374
उत्तराखंड	839	987	872	2698
पश्चिम बंगाल	2911	3834	2309	9054
योग:-	49964	89796	28145	167905
